



“वर्तमान भारत में ग्रामीण स्तर के विद्यार्थियों की शिक्षा का महत्व व समस्याओं पर अध्ययन”

¹Akhil Kumar Singh, ²Dr. S.P. Tripathi ³Dr. Neeru Verma

¹Research Scholar (Education)

²⁻³Research Guide, Bhagwant University, Ajmer, Rajasthan, India

Email- Email- bajarangbali198@gmail.com

Edu. Research Paper-Accepted Dt. 30 June 2023

Published : Dt. 15 Aug. 2023

सारा”।

जीवन में सफलता प्राप्त करने और कुछ अलग करने के लिए शिक्षा सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। यह हमें जीवन के कठिन समय में चुनौतियों से सामना करने में सहायता करता है। मनुष्य के जीवन में जितना महत्व भोजन, कपड़े, हवा और पानी का है, उससे कहीं अधिक महत्व शिक्षा का है इसीलिए हमेशा ये ही कहा जाता है कि शिक्षा का मानव जीवन में बहुत महत्व है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे मनुष्य में ज्ञान का प्रसार होता है। इंसान की बुद्धि का विकास शिक्षा अर्जित करने से ही होता है। शिक्षा मानव जीवन की एक महत्वपूर्ण इकाई है। पूरी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान प्राप्त किया गया ज्ञान हम सभी और प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के प्रति आत्मनिर्भर बनाता है। यह जीवन में बेहतर संभावनाओं को प्राप्त करने के अवसरों के लिए विभिन्न दरवाजे खोलती है जिससे कैरियर के विकास को बढ़ावा मिले। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा बहुत से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। यह समाज में सभी व्यक्तियों में समानता की भावना लाती है और देश के विकास और वृद्धि को भी बढ़ावा देती है। बेहतर शिक्षा सभी के लिए जीवन में आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है। यह हमें आत्मविश्वास विकसित करने के साथ ही हमारे व्यक्तित्व निर्माण में भी सहायता करती है। स्कूली शिक्षा सभी के जीवन में महान भूमिका निभाती है। पूरे शिक्षा तंत्र को प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षा जैसे को तीन भागों में बाँटा गया है।

भाब्द कुर्जीं- अर्जित, आत्मनिर्भर, जागरूकता, समानता, विकास, वृद्धि।



प्रस्तावना—

शहरों में शिक्षा प्राप्त कर पाना आसान है, लेकिन क्या आपने ग्रामीण क्षेत्रों की उन नन्हीं बेटियों का सोचा है, जो कम उम्र में ही शिक्षा से वंचित कर दी जाती हैं। भारत ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा बहुत से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। यह समाज में सभी व्यक्तियों में समानता की भावना लाती है और देश के विकास और विद्या को भी बढ़ावा देती है। शिक्षा के जरिए ही भावी राष्ट्र का निर्माण होता है ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता एक सामान्य विषय नहीं था इसके लिए इसके लिए शिक्षक को दोषी माना जाता था लेकिन अब परिस्थितियों को देखते हुए शिक्षक भी पूर्ण ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और सरकार भी पूर्ण सहयोग प्रदान कर रही हैं बच्चों को फ्री में बुक ,ड्रेस ,सार्टिकिल ,और भी अन्य शुविधाय दे रही हैं। शिक्षा के सभी स्तर अपना एक विशेष महत्व और स्थान रखते हैं। हम सभी अपने बच्चों को सफलता की ओर जाते हुए देखना चाहते हैं, जो केवल अच्छी और उचित शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। ग्रामीण शिक्षा के क्षेत्र में आज भी लोग इंडिया के ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सोच को विकसित नहीं कर पाए हैं जिस कारण से बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में अपनी दक्षताओं की पूर्ति करने में परेशानी आती हैं क्यों की आज भी ग्रामीण क्षेत्र में पालक इतने सक्षम नहीं हैं की अपनी बच्चे की शिक्षा के लिए वह शिक्षक से मिल सके और उनसे अपने बच्चे के शिक्षा के लिए चर्चा कर सके। क्यों की ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर मजदूर वर्ग रहते हैं और उनको अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए दुसरों पर निर्भर रहना पड़ता है जिससे वह बच्चों को समय नहीं दे पते।

ग्रामीण शिक्षा का महत्व—

सबसे पहले, शिक्षा पढ़ने और लिखने की क्षमता सिखाती है। पढ़ना –लिखना शिक्षा की पहली सीढ़ी है। अधिकांश जानकारी लिखित रूप में होती है, यदि आप में शिक्षा का अभाव है या लेखन कौशल की कमी है, तो आप समाज से दूर हैं, समाज में होने वाली गतिविधियों से दूर हैं। हम अपने अभिभावकों और शिक्षक के प्रयासों के द्वारा अपने जीवन में अच्छे शिक्षित व्यक्ति बनते हैं। वे वास्तव में हमारे शुभ चिंतक हैं, जिन्होंने हमारे जीवन को सफलता की ओर ले जाने में मदद की। आजकल, शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए बहुत सी सरकारी योजनाएं चलायी जा रही हैं ताकि, सभी की उपयुक्त शिक्षा तक



पहुँच संभव हो। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को शिक्षा के महत्व और लाभों को दिखाने के लिए टीवी और अखबारों में बहुत से विज्ञापनों को दिखाया जाता है क्योंकि पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में लोग गरीबी और शिक्षा की ओर अधूरी जानकारी के कारण पढ़ाई करना नहीं चाहते हैं।

ग्रामीण शिक्षा की आवश्यकता

भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकांश जनता गाँवों में रहती है। इसलिए देश के विकास के लिए गाँवों की समस्याओं का समाधान परमावश्यक है। वर्तमान काल में भारत के गाँवों में बहुत सी समस्याएँ विद्यमान हैं जिन्होंने अभी तक स्वर्ग समान इन गाँवों को नरक-तुल्य बना रखा है। यूँ तो देश के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में गाँवों की समस्याओं में कुछ-न-कुछ स्थानीय अन्तर पाया जाता है, परन्तु इस स्थानीय अन्तर को छोड़कर भी कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिन्हें देश के सभी गाँवों की सामान्य समस्याएँ माना जा सकता है। ऐसी प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं—

(1) खेती की असन्तोषजनक दशा— यद्यपि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तथापि यहाँ पर खेती की दशा दयनीय है। खेतों के निरन्तर बिखण्डन के कारण अनार्थिक जोतों की संख्या बढ़ रही है। किसानों को खेती के नए-नए प्रयोगों, नए औजारों, नई पद्धतियों आदि का ज्ञान नहीं है। वे आज भी पुराने ढंग से खेती करते हैं और खेती के उन्नत तथा आधुनिक ढंगों से अनभिज्ञ होने के कारण खेती की समस्याओं को निपटाने के लिए पुराने दकियानूसी उपायों को ही काम में लाते हैं। इससे प्रति एकड़ उपज बहुत कम रहती है और वर्ष में फसलों की संख्या भी अन्य देशों की अपेक्षा कम है।

(2) कुटीर उद्योगों की कमी— भारत के गाँवों में कुटीर उद्योगों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है और न ही लोगों को उनके सम्बन्ध में नई-नई विधियों का ज्ञान है। मुर्गीपालन, मत्स्य पालन, कपड़ा बनाना आदि कुटीर उद्योगों का भारतीय गाँवों में समुचित विकास नहीं हुआ है और जहाँ कहीं ये हैं भी, पुराने दंगों को अपनाए जाने के कारण उनकी दशा बही असन्तोषजनक है।

(3) गरीबी और बेरोजगारी— भारतीय गाँवों में गरीबी और बेरोजगारी के भयंकर अभिशाप स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। असंख्य ग्रामीण ऐसे हैं जिनको दो वक्त पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता। किसी भी गाँव में चले जाइए वहाँ आपको गलियों में चिथड़े पहने खेलते हुए मैले बालक-बालिकाओं को देखकर उनकी गरीबी का सहज ही आभास हो जायेगा। अधिकतर मकान कच्चे, अस्वास्थ्यकर और छोटे दिखाई पड़ेंगे भारत में अधिकांश ग्रामीणों को साल भर रोजगार नहीं मिलता। वे साल में कई महीने बेकार रहते



हैं। गरीबी और बेकारी ने मिलकर भारतीय ग्रामीणों की दुर्दशा कर रखी है।

(4) गन्दगी— भारत में साफ सुथरे गांवों की संख्या बहुत कम है। अधिकतर गाँवों में घोर गन्दगी दिखाई पड़ती है। गलियों में खुली नालियों में गन्दा बदबूदार पानी बहता रहता है। बरसात में यह पानी फैलकर और गली में पड़े मल—मूत्र से मिलकर साक्षात् नरक का दृश्य उपस्थित करता है। गलियों के पक्के होने की बात ही क्या अधिकतर गाँवों में पक्की सड़कें भी नहीं हैं।

(5) ऋणग्रस्तताकृ भारत के गांवों में ऋणग्रस्तता का अभिशाप गाँव वालों को जीवन भर फलने—फूलने नहीं देता। कुछ थोड़े से साहूकार उनसे उल्टे—सीधे कागज पर अंगूठा लगवाकर उन्हें जीवन भर लूटते हैं।

(6) फूट और मुकदमेबाजी— साहूकारों के साथ वकील भी इस लूट में शामिल हैं। आज गाँव वाले जरा—जरा सी बात पर मारपीट और कत्ल तक कर डालते हैं और छोटी—छोटी बातों को लेकर सालों—साल एक दूसरे के विरुद्ध मुकदमे लड़ते रहते हैं तथा अपने बाल बच्चों का दूध—घी छीनकर वकीलों की जेबें भरा करते हैं।

(7) अन्धविश्वास और अज्ञान— गाँव वालों की प्रगति और समृद्धि में सबसे बड़े बाधक अन्धविश्वास और अज्ञान है। इस कारण जहाँ वे जीवनयापन के नए—नए उपाय न अपनाकर जीवन भर गरीबी में सड़ा करते हैं वहीं आसानी से छूतों के चंगुल में फंस जाते हैं। वे अनावश्यक बातों में बहुत—सा रूपया फूंक देते हैं और जीवन की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते।

उपयुक्त ग्रामीण समस्याओं के कारणों का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि उनके मूल में सबसे बड़ा कारण अशिक्षा है। अशिक्षा के कारण गाँव वालों को नए—नए वैज्ञानिक आविष्कारों का पता नहीं चल पाता। इससे खेती और कटीर उद्योगों का समुचित विकास नहीं हो पाता। अशिक्षा के कारण ग्रामीण लोग स्वास्थ्य के मूल सिद्धान्तों को नहीं जानते और अनजाने ही रोगों के शिकार हो जाते हैं। अशिक्षा के कारण वे सुसंस्कृत नहीं हो पाते और गन्दे रहते हैं। ‘अशिक्षा’ अन्धविश्वास और अज्ञान का मूल आधार है।

ग्रामीण स्तर पर शिक्षा की प्रमुख समस्याएँ

- आज भी ऐसे ग्रामीण स्कूल हैं जहाँ कमरों व डेस्क—बेंच जैसी मूलभूत सुविधाएँ भी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हैं।
- बहुत से स्कूलों में बच्चे बरामदों व पेड़ों के नीचे बैठकर ही पढ़ते नजर आते हैं। गर्मी के मौसम में बच्चों को पीने के पानी के लिये भी भटकना पड़ता है।



- शौचालय स्कूलों में बनाए अवश्य गए हैं, लेकिन पानी के अभाव में उनमें साफ—सफाई रख पाना मुश्किल हो जाता है।
- सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करवाने का प्रावधान है, लेकिन इस दिशा में कोई बेहतर स्थिति दिखाई नहीं देती। शिक्षा सत्र शुरू होने के तीन महीने बाद तक भी पहली से आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल पातीं।
- ग्रामीण स्कूलों में मिड—डे मील संचालन के तौर—तरीकों पर भी सवाल उठाए जाते हैं। स्कूलों में बच्चों को खाना खिलाने में ही शिक्षकों का काफी समय व्यर्थ हो जाता है। आधिकारिक स्तर पर मिड—डे मील स्कीम के कार्यान्वयन को लेकर ठोस योजना का अभाव एक बड़ा गतिरोध है।
- देश के बहुत से ग्रामीण स्कूल ऐसे हैं जहाँ बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से एड्यूसेट के उपकरण लगाए गए हैं। लेकिन भारी—भरकम खर्च से लगाए गए ये उपकरण अधिकांश स्कूलों में मात्र शो—पीस बनकर रह गए हैं।
- ग्रामीण सरकारी स्कूलों की छवि गरीबों और अशिक्षितों के बच्चों के स्कूल वाली बन गई है, जो पूरी तरह शिक्षकों को दया पर निर्भर हैं।
- आज भी शिक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा स्कूलों में अध्यापकों के वेतन और प्रशासन पर ही खर्च होता है। फिर भी विश्व में बिना अनुमति अवकाश लेने वाले अध्यापकों की संख्या भारत में सबसे अधिक है।
- ग्रामीण स्कूलों में अक्सर यह देखने में आता है कि अध्यापक आते ही नहीं हैं और चार में से एक सरकारी स्कूल में रोज कोई—न—कोई अध्यापक छुट्टी पर होता है।

नई एकीकृत शिक्षा योजना

केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च, 2020 के लिये नई एकीकृत शिक्षा योजना बनाई है। यह योजना आज भारत के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लाभदायक साबित हो रही है। इस योजना में सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षण अभियान समाहित हैं। इस योजना को सफल बनाने के लिये 75 हजार करोड़ रुपए मंजूर किये गए हैं। इस योजना का लक्ष्य सबको



शिक्षा, अच्छी शिक्षा देना तथा पूरे देश में प्री-नर्सरी से लेकर 12वीं तक की शिक्षा सुविधा सबको उपलब्ध कराने के लिये सभी राज्यों के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की मदद करना है। एकीकृत स्कूली शिक्षा योजना में शिक्षकों और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रामीण व शहरी हर तरह की स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने पर खास जोर दिया गया है।

योजना के प्रमुख उद्देश्य

- गुणवत्ता युक्त शिक्षा की व्यवस्था और छात्रों के सीखने की क्षमता में वृद्धि।
- स्कूली शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक असमानता के अंतर को कम करना।
- स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समग्रता सुनिश्चित करना।
- स्कूली व्यवस्था में न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना।
- शिक्षा के साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना।
- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, 2009 को लागू करने के लिये राज्यों की मदद करना।
- राज्यों की शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों, शिक्षण संस्थाओं तथा जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थाओं को शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये नोडल एजेंसी के रूप में सशक्त और उन्नत बनाना।

निष्कर्ष

शिक्षा लोगों के मस्तिष्क को उच्च स्तर पर विकसित करने का कार्य करती है और समाज में लोगों के बीच सभी भेदभावों को हटाने में मदद करती है। यह हमारी अच्छा अध्ययन कर्ता बनने में मदद करती है और जीवन के हर पहलू को समझने के लिए सूझ—बूझ को विकसित करती है। यह सभी मानव अधिकारों, सामाजिक अधिकारों, देश के प्रति कर्तव्यों और दायित्वों को समझने में भी हमारी सहायता करता है। गांवों में शिक्षा का प्रसार ग्रामीण समस्याओं को सुलझाने के लिए गाँवों में प्राथमिक शिक्षा तथा समाज शिक्षा का प्रसार परमावश्यक है। प्राथमिक शिक्षा बालकों को समाज के योग्य नागरिक के रूप में विकसित करेगी। समाज—शिक्षा से वयस्कों का सर्वांगीण विकास होगा। समाज—शिक्षा में साक्षरता के साथ—साथ कृषि और उद्योगों की शिक्षा, स्वारक्ष्य, मनोरंजन, घरेलू तथा आर्थिक जीवन और नागरिकता की शिक्षा भी



होनी चाहिए। इनमें कक्षा की पढ़ाई के अलावा रेडियो, नाच—गाने, कठपुतली का तमाशा, प्रदर्शनी, भजन—कीर्तन तथा अन्य उपायों से भी काम लिया जाना चाहिए। समाज—शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए और व्यावहारिक उपायों द्वारा दी जानी चाहिए। इसके लिए शिक्षक विशेष प्रकार के प्रशिक्षण महाविद्यालयों में प्रशिक्षित होने चाहिए। प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत भारतीय गांवों के बालकों को सर्वांगीण शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची—

- ए यादव सुबह सिंह, यादव जे.पी., यादव एच.एस., (1991), 'भारतीय शिक्षा प्रवृत्तियाँ व्यायाम', पोइंटर पब्लिशर्स, जयपुर. पृ.क्र. 115–118. .
- ए किसलय शरदेन्द्र, प्रसाद गोविन्द, (2006), 'भारत में शिक्षा का विकास', डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, पृ.क्र. 189
- ए सिंह शिवबहाल, (2010), 'विकास का समाजशास्त्र', रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, पृ.क्र. 66.
- ए शर्मा रामनाथ, शर्मा राजेन्द्र कुमार, (2006), 'शैक्षिक समाजशास्त्र', एटलांटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली.
- ए बक्शी एन.एस., (2007), 'उदीयमान भारतीय समाज एवं शिक्षा', प्रेरणा प्रकाशन, दिल्ली.
- ए मोदी अनिता, (2012), 'ग्रामीण भारत बदलती तस्वीर', वाईकिंग बुक्स, जयपुर.